

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2013/फाल्गुन 30, 1934	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 299
No. 49]	DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2013/PHALGUNA 30, 1934	[N.C.T.D. No. 299

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2013

सं. 21(04)/2013/एल ए एस-IV/वि./1854.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या (-04) 2013

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर
(संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा
में दिनांक 21 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित किया गया)

2013 का विधेयक संख्या 04

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में आगे संशोधन हेतु विधेयक

एक

विधेयक

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा भारतीय गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .— (1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होता है।

(3). यह अधिनियम सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा, सिवाय
(क) इस अधिनियम की धारा 12 जो जून, 2012 के 18वें दिन से प्रभावी मानी जायेगी
(ख) इस अधिनियम की धारा 13 जो मार्च, 2013 के 31वें दिन से प्रभावी मानी जायेगी।

2. धारा 2 में संशोधन :—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) जिसे इसके बाद "मूल अधिनियम" कहा गया है की धारा 2 की उपधारा (1) में :—

(i) खंड (ज़ ग) में उपखंड (viii) में संख्या (ix) के लिए संख्या (vii) तथा "धारा" शब्द के स्थान पर "उपधारा" शब्द को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) खंड (ज़ घ) में उपखंड (v) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944(1944 का 1) या सीमा कर अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम) के अंतर्गत वसूलनीय या वसूल की गई शुल्क की राशि चाहे यह शुल्क विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय हो, तथा"

- (iii) खंड (य घ) के उपखंड (vii) में "व्याख्या-1" से पूर्व एक परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"उपबंध है कि जहां व्यापारी भारत के क्षेत्र में आयातित सामान की बिक्री करता है, बिक्री मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा:-

(क) व्यापारी द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली मूल्यगत बिक्री;

(ख) संबंधित सामान के आयात के समय सीमा शुल्क के समय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्य।"

3. धारा 3 में संशोधन :- मूल नियमावली की धारा 3 में उपधारा (4) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) व्यापारी के सकल कर का भुगतान प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति के इक्कीस दिन के भीतर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- कर भुगतान का दायित्व इस प्रावधान के कारण पैदा होता है तथा यह रिटर्न जमा करने पर या व्यापारी को निर्धारण का नोटिस दिए जाने पर निर्भर नहीं है।"

4. धारा 9 में संशोधन :- मूल नियमावली की धारा 9 में-

- (i) उपधारा (9) के खंड (क) में उपखंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(ii) "उक्त इनपुट कर का शेष $2/3$ भाग समान अनुपात में संबंधित कर अवधियों में तत्काल आगामी दो वित्तीय वर्षों में";

- (ii) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"(11) इस धारा की उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य ग) के उपखंड (vi) में यथापरिभाषित-बिक्री के लिए प्रयोग सामान का कर जमा निम्न प्रकार से अनुमत होगा:

(क) कर अवधि में ऐसी वस्तुओं पर इनपुट कर का $1/4$ चौथाई, उसी कर अवधि में;

(ख) तीन आसन्न उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सम्बद्ध कर अवधियों का ऐसे इनपुट कर का शेष $3/4$ समान अनुपात में।"

5. धारा 16 में संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में -

(i) प्रथम परन्तुक में, जहां कहीं शब्द "धारा" आता है, उसके स्थान पर शब्द "उपधारा" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ii) परन्तुक के उपरान्त निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“आगे शर्त यह है कि यदि सरकार ने इस धारा की उपधारा (12) के अन्तर्गत व्यापारियों की किसी श्रेणी के लिये समझौता/समाधान योजना अधिसूचित की है, तो ऐसे व्यापारियों के लिये इस उपधारा के अन्तर्गत कर के भुगतान करने के लिये कोई विकल्प नहीं रहेगा।”

6. धारा 18 में संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में शब्द “दस” के स्थान पर शब्द “बीस” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. धारा 22 में संशोधन :— मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(8) आयुक्त, तीन माह तक के अन्तरालों पर विभागीय वेबसाइट पर जिन पंजीकृत व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है उनके ऐसे यथानिर्धारित विवरण प्रदर्शित करेंगे।”

8. धारा 26 में संशोधन :— मूल अधिनियम की धारा 26 में —

- (i) उपधारा (1) में शब्द “तथा पद्धति” अन्त में जोड़े जाएंगे।
(ii) उपधारा (2) और उपधारा (3) हटाई जाएंगी।

9. धारा 34 में संशोधन:— मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) जिनकी व्यक्ति ने इस अधिनियम की धारा 26 या 28 के अन्तर्गत एक या अधिक कर अवधियों को मिलाकर वर्ष के अन्त में कोई विवरणी प्रस्तुत की है; अथवा”

10. धारा 36क में संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 36क में—

- (i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“शर्त यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपंजीकृत ठेकेदारों की स्थिति में कर कटौती की दर (स्रोत पर कटौती) 6 प्रतिशत होगी।”

- (ii) उपधारा (1 क) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“इस अधिनियम के अन्तर्गत अपंजीकृत उप-ठेकेदारों की स्थिति में दर (स्रोत पर कर कटौती) 6 प्रतिशत होगी।”

11. धारा 44 में संशोधन:— मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (ख) में शब्द “उपायुक्त मूल्य संवर्धित कर” के उपरान्त शब्द “तथा सहायक आयुक्त मूल्य संवर्धित कर” सन्निविष्ट किए जाएंगे।

12. धारा 58क में संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 58क में—

- (i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) को उपबंध का, इसमें कुछ भी रहते हुए, प्रभाव होगा कि व्यापारी के खाते इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के किसी अन्य उपबंध के अन्तर्गत लेखा परीक्षा करा ली गई है या अन्यथा।"

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत अभिलेख की जांच और लेख परीक्षा के व्यय एवं प्रासंगिक व्यय (लेखाकार या लेखाकार के एक के पेनल या व्यवसायी या व्यवसायियों के पेनल के पारिश्रमिक सहित) आयुक्त द्वारा ज्ञात करके भुगतान किया जाएगा और यह निर्धारण अन्तिम होगा।"

13. धारा 47 में संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (10) में शब्द "आठ" के स्थान पर शब्द "दस" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. धारा 86 में संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (18) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(18) यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अनुपालन के प्रति विफल रहता है, तो व्यापारी अपनी कुल बिक्री या एक लाख रुपये की राशि, जो भी कम हो, के एक प्रतिशत के बराबर राशि, अर्थादंड के रूप में भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा।"

15. धारा 87 में संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (5) के बाद निम्नलिखित उपधारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(6) यदि—

(क) कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत अर्थादंड के भुगतान के प्रति उत्तरदायी है; और

(ख) व्यक्ति धारा 60 के अन्तर्गत कार्रवाईयों के दौरान कर त्रुटि के होने संबंधी लिखित में आयुक्त का स्वैच्छा से प्रकट करता है; और

(ग) उक्त कार्रवाईयों के समापन के तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी कर त्रुटि का भुगतान करता है;

माने गए तथा भुगतान किए गए कर के स्थान पर अन्यथा देय अर्थादंड की राशि अस्सी प्रतिशत तक कम की जाएगी।"

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

पंजाब आबकारी अधिनियम के स्थान पर दिल्ली आबकारी अधिनियम के क्रियान्वयन के कारण परिवर्तन करने के लिए धारा 2 का संशोधन अभिष्ट है। "बिक्री मूल्य" की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आयातित वस्तुओं के मामले में एक परन्तुक जोड़ा गया है।

वर्तमान में, दो तरह के व्यापारी हैं अर्थात् मासिक और तिमाही। दिल्ली मूल्य संबंधित कर नियमावली में संशोधन के लिए एक पृथक प्रस्ताव द्वारा विभाग ने प्रस्ताव किया है कि दो कर अवधियों

अर्थात् "तिमाही" तथा "मासिक" के स्थान पर केवल एक कर अवधि अर्थात् "तिमाही" होगी। इससे व्यापारियों को बारह के स्थान पर केवल चार रिटर्न फाइल करने की सुविधा होगी। यह भी प्रस्तावित है कि व्यापारी से प्रत्येक माह की समाप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर कर जमा करना अपेक्षित होगा लेकिन इससे व्यापारी पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार की ओर से व्यापारी द्वारा संग्रहित कर उपभोक्ताओं से उसी कर के संग्रहण के पश्चात् ही सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।

धारा 9 में संशोधन, उपयोग आधार पर अधिकारपूर्वक वस्तुओं की बिक्री में लगे व्यापारियों के लिए इनपुट कर क्रेडिट में राहत देने का प्रस्ताव करता है। यह संशोधन दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय का पालन करता है। यह पूंजीगत वस्तुओं पर कर क्रेडिट के दावे की अस्पष्टता को भी दूर करता है, थोड़ा संशोधन भी प्रस्तावित है।

अब तक वर्तमान समझौता स्कीम व्यापारियों और ठेकेदारों के लिए बनाई गई। सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्य संविदा व्यापारियों के लिए एक नई समझौता स्कीम प्रस्तुत की है। अतः धारा 16 में संशोधन, कार्य संविदा व्यापारियों को सामान्य समझौता स्कीम से बाहर निकालने का प्रस्ताव करता है। यह अस्पष्टता को दूर करेगा।

दिल्ली पहला राज्य है जिसमें धारा 18 में संशोधन द्वारा मार्जिनल व्यापारियों को बड़ी राहत पहुंचाने के लिए 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक पंजीकरण के लिए प्रारंभिक सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

औसतन प्रत्येक माह 2,000 व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो जाता है। धारा 22 में संशोधन करके विभागीय वेबसाइट पर रद्द किए गए व्यापारियों का विवरण डालने का प्रस्ताव है। यह राजपत्र में अधिसूचनाओं के लिए वर्तमान जरूरत के स्थान पर प्रस्तावित है।

इस समय इलैक्ट्रॉनिक रिटर्न के अलावा व्यापारियों को रिटर्न की हार्ड कॉपी भी जमा करानी होती है। अनुलिपिकरण (डुप्लीकेसी) से बचने के लिए धारा 26 में संशोधन प्रस्तावित है। निर्धारण प्रक्रिया को युक्तिपरक बनाने के लिए धारा 34 में संशोधन द्वारा वित्तीय वर्ष की समस्त विवरणियों के लिए एक समान समयावधि बनाने का प्रस्ताव है।

कार्य संविदा में लगे पंजीकृत व्यापारियों के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से मूल स्रोत पर कर कटौती की जाती है। धारा 36 में संशोधन से अपंजीकृत व्यापारियों से 6 प्रतिशत अर्थात् उच्चतम दर से मूल स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है।

विभाग में अधिकारियों के पदनामों को पुनः पदनामित किया जाएगा। इसलिए धारा 44 में संशोधन किया गया है।

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 से संबंधित लंबित अपीलों के लिए निर्धारित समय सीमा 31 मार्च, 2013 है। धारा 74 में संशोधन करके अवधि को दो वर्षों तक बढ़ाना प्रस्तावित है। छूट योजना के माध्यम से अपीलों का निपटान अगले वर्ष किया जा सकता है।

मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में, व्यापारी द्वारा भरी गई विवरणी को स्व-निर्धारण के रूप में माना है। विभाग ने बड़े व्यापारियों के लिए एक लेखा रिपोर्ट विनिर्धारित की है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 86 में संशोधन करके अर्थदंड 10,000/—रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/—रुपये या व्यापारी की सकल आय का एक प्रतिशत जो भी कम हो, को करने का प्रस्ताव है इससे विभाग को रिफंड और निर्धारणों की सामान्य चूक को दूर करने में मदद मिलेगी।

व्यापारियों को राहत देने के लिए क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान कर त्रुटियों का स्व-प्रकटीकरण करने पर तथा देय कर जमा कराने पर दंडात्मक उपबंधों से छूट देने के लिए धारा 87 में संशोधन प्रस्तावित है।

(शीला दीक्षित)

मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री

नई दिल्ली:

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 में किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नए पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है।

प्रत्यायोजन विधान से संबंधी ज्ञापन

मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 में अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

गृह पुलिस (2) विभागअधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2013

सं. एफ. 11/21/2000/गृह पुलिस-2/पार्ट फाइल/2244.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथाविस्तारित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या XXX) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री ए.के. गाबा, वरिष्ठ लोक अभियोजक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, ईओ-II, नई दिल्ली को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथाविस्तारित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3 व धारा 4 के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 489 ख तथा 489 ग के साथ पठित धारा 120 ख के अन्तर्गत मामला संख्या आर सी 220 2011 ई 0004 ईओयू 6 के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय में अभियोजन चलाने के लिये लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लोधी रोड, नई दिल्ली की आर्थिक अपराध-II शाखा में दिनांक 16-06-2011 को पंजीकृत था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. के. तिवारी, उप-सचिव

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2013

सं.फा.7/433/नीति-II/वैट/2012/1429-38.—अधिसूचना संख्या सं. फा 7/433/नीति-II/वैट/2012/585-595 दिनांक 05-09-2012 तथा इसके बाद में जारी की गई अधिसूचनाओं, जो कि फार्म टी-2 में दी जाने वाली सूचना से संबंधित थी, के अधिक्रमण में, मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप-धारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि व्यापारी द्वारा दिल्ली के बाहर से खरीदी गई अथवा स्टॉक अंतरण के द्वारा प्राप्त की गई सभी वस्तुओं के लिये, वस्तुओं के दिल्ली की सीमा में वास्तविक आगमन से पूर्व, इनवाइस एवं जी.आर. नोट का विवरण, अपने लॉगिन आई डी और पासवर्ड का प्रयोग करके, ऑन लाइन दाखिल किया जाये। इस प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न संशोधित प्रपत्र टी-02 का प्रयोग किया जायेगा।

इस अधिसूचना के लागू होने की प्रभावी तिथि निम्न प्रकार से होगी।

व्यापारी वर्ग	प्रभावी तिथि
पूर्णतया कर मुक्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों को छोड़कर, जिन व्यापारियों की सकल बिक्री रुपये 10 करोड़ या उससे अधिक है।	01-04-2013
अन्य सभी व्यापारी	बाद में अधिसूचित की जाएगी।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

प्रपत्र टी-2

इनवाइस विवरण :

इनवाइस संख्या: _____ दिनांक: _____ कुल इनवाइस मूल्य _____

खरीद का प्रकार: _____

विक्रेता की पहचान:—

टिन :—

नाम :—

पता :—

राज्य :—

नगर:—

वस्तु का विवरण :-

वस्तु-वार विवरण का कुल जोड़ डीवैट-30 में दर्ज किये जाने योग्य खरीद के मूल्य के बराबर होना चाहिए ।

वस्तु का नाम	मात्रा	इकाई
_____	_____	_____

मूल्य प्रति इकाई	मूल्य	कुल मूल्य
_____	_____	_____

यातायात का प्रतिरूप: 0सड़क मार्ग द्वारा 0कोरियर द्वारा 0रेल द्वारा 0पाइप लाइन द्वारा 0वायु मार्ग द्वारा 0इंटरनेट द्वारा

डिस्पेच संबंधी विवरण:-

वस्तुओं के डिस्पेच का स्थान _____

वस्तुओं की डिलीवरी का स्थान _____

ट्रांसपोर्टर की पहचान:-

नाम _____

पता _____

राज्य _____

नगर _____

वाहन संख्या _____ (चार अंको की संख्या)

जी0 आर0/आर0आर0/कोरियर/एयरवेज संख्या _____

दिनांक _____

1205 DG/13-3

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st March, 2013

No. 21 (04)/2013/LAS-IV/Leg./1854.—The following is published for general information :—

BILL NO. 04 OF 2013

**The Delhi Value Added Tax
(Amendment) Bill, 2013**

**(As introduced in the Legislative Assembly of the
National Capital Territory of Delhi on 21st March, 2013)**

BILL NO. 4 OF 2013

THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the official Gazette, appoint, except (a) Section 12 of this Act shall be deemed to have come into force on the 18th day of June, 2012. (b) Section 13 of this Act shall be deemed to have come into force on the day of 31st March, 2013.
2. Amendment of section 2.- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereinafter referred to as 'the principal Act', in section 2, in sub-section (1), -
 - (i) in clause (zc), in sub-clause (viii), for the number '(ix)', the number '(vii)' and for the word 'section', the word 'sub-section', shall respectively be substituted;
 - (ii) in clause (zd), for sub-clause (v), the following shall be substituted, namely:-

"amount of duties levied or leviable on the goods under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the Customs Act, 1962 (52 of 1962), or the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010) whether such duties are payable by the seller or any other person; and"
 - (iii) in clause (zd), in sub-clause (vii), before the 'Explanation-1', a Proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the dealer makes sale of goods imported into the territory of India, the sale price shall be greater of the following:
(a) *the valuable consideration received or receivable by the dealer;*
(b) *value determined by the Custom authorities for payment of custom duty at the time of the import of such goods."*

3. Amendment of section 3.- In the principal Act, in section 3, for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) The net tax of a dealer shall be paid within twenty one days of the conclusion of each calendar month.

Explanation.- The obligation to pay the tax arises by virtue of this provision and is not dependent on furnishing a return, nor on the issue of a notice of assessment to the dealer."

4. Amendment of section 9. - In the principal Act, in section 9,-
(i) in sub-section (9), in clause (a), for sub-clause(ii), the following shall be substituted, namely, -

(ii) "balance $2/3^{\text{rd}}$ of such input tax, in equal proportions, in corresponding tax periods, in two immediately successive financial years .";

- (ii) after sub-section (10), the following sub-section, shall be inserted, namely: -

"(11) Subject to sub-section (1), (2) and (3) of this section, the tax credit of goods to be used for sale, as defined in sub-clause (vi) of clause (zc) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, shall be allowed as follows:

- (a) $1/4^{\text{th}}$ of the input tax on such goods arising in the tax period, in the same tax period;
- (b) balance $3/4^{\text{th}}$ of such input tax, in equal proportions, in corresponding tax periods, in three immediately successive financial years."

5. Amendment of section 16.- In the principal Act, in section 16, in sub-section(1), -

- (i) in the first proviso, for the word 'section', wherever occurring, shall be substituted by the words "sub-section".
- (ii) after the proviso, the following proviso, shall be inserted, namely:-

"PROVIDED FURTHER that in case the Government has notified a composition scheme for a class of dealers under sub-section (12) of this Section, such dealers shall not have an option to pay tax under this sub-section."

6. Amendment of section 18.- In the principal Act, in section 18, in sub-section (2), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

7. Amendment of section 22 - In the principal Act, in section 22, for sub-section (8), the following shall be substituted, namely:-

"(8) The Commissioner shall, at intervals not exceeding three months, host on the departmental website, such particulars as may be prescribed, of registered dealers whose registration has been cancelled."

8. Amendment of section 26. - In the principal Act, in section 26, -

- (i) in sub-section (1), the words "and manner" shall be added in the end.
- (ii) sub-section (2) and sub-section (3) shall be omitted.

9. Amendment of section 34.- In the principal Act, in section 34, in sub-section (1), for clause (a) the following shall be substituted, namely:-

"(a) the end of the year comprising of one or more tax periods for which the person furnished a return under section 26 or 28 of this Act; or"

10. Amendment of section 36A.- In the principal Act, in section 36A,-

- (i) in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"PROVIDED that the rate of deduction of tax (TDS) shall be 6% in case of contractors not registered under this Act."

- (ii) in sub-section (1A), the following proviso shall be inserted, namely: -

"PROVIDED that the rate of deduction of tax (TDS) shall be 6% in case of sub-contractors not registered under this Act."

11. Amendment of section 44.- In the principal Act, in section 44, in sub-section (2), in clause (b), after the words "Deputy Commissioner of Value Added Tax", the words "and the Assistant Commissioner of Value Added Tax" shall be inserted.

12. Amendment of section 58A.- In the principal Act, in section 58A,-

- (i) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely: -

"(2) The provision of sub-section (1) shall have effect notwithstanding that the accounts of the dealer have been audited under any other provision of this Act or any other law for the time being in force or otherwise."

- (ii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely: -

"(4) The expenses of, and incidental to, the examination and audit of records under sub-section (1), (including the remuneration of the accountant or a panel of accountants or professional or panel of professionals) shall be determined and paid by the Commissioner and that determination shall be final."

13. Amendment of section 74.- In the principal Act, in section 74, in sub-section (10), for the word "eight", the word "ten" shall be substituted.

14. Amendment of section 86.- In the principal Act, in section 86, for sub-section (18), the following shall be substituted, namely:-

"(18) If, any dealer fails to comply with the provisions of section 49 of this Act, the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to one percent of his turnover or a sum of one lakh rupees, whichever is less."

15. Amendment of section 87.- In the principal Act, in section 87, after sub-section (5), the following sub-section, shall be inserted, namely:-

"(6) If -

- (a) a person is liable to pay penalty under section 86 of this Act; and
- (b) the person voluntarily discloses to the Commissioner, in writing, the existence of the tax deficiency, during the course of proceedings under section 60; and

(c) makes payment of such tax deficiency within three working days of the conclusion of the said proceedings;

the amount of the penalty otherwise due, against the admitted and paid tax, shall be reduced by eighty per cent."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment of section 2 intends to make changes due to implementation of the Delhi Excise Act replacing the Punjab Excise Act. To make the definition of 'Sale Price' more clear, a Proviso has been added in case of imported goods.

At present, there are two types of dealers viz. monthly and quarterly. By a separate proposal for amendment in the DVAT Rules, the department has proposed that henceforth, instead of two Tax Periods i.e. 'a quarter' and 'a month', there shall be only one Tax Period i.e. 'a quarter'. This will facilitate the dealers to file only four returns instead of twelve. It is proposed that the dealers shall be required to deposit the tax within twenty

one days of the conclusion of each calendar month but this will not put any extra burden on the dealer because the tax collected by the dealer on behalf of the government is deposited in the government treasury after collecting the same from the customers.

Amendment in section 9 is proposed to give relief of input tax credit to the dealers engaged in the selling of goods on Right to Use basis. This is an amendment following Delhi High Court decision. Also, to remove the ambiguity in claiming tax credit on capital goods, a minor amendment is also proposed.

Till recently, the existing composition scheme was formulated for traders and contractors. The government has introduced a new composition scheme for different types of works contract dealers. Hence, amendment in section 16 is proposed to exclude the works contract dealers from general composition scheme. This will help avoid ambiguity.

Delhi is the first State to propose the enhancement of threshold limit for registration from Rs.10 lakhs to Rs.20 lakhs, thereby giving a major relief to the marginal dealers by amending section 18.

On an average, more than 2,000 dealers' registration is cancelled every month. It is proposed to host the particulars of cancelled dealers on the departmental website by amending section 22. This is proposed to do away with the current need for gazette notifications, in this regard and thus simplify the procedure.

Presently, in addition to electronic return, dealers have to file hard copy of the same. To avoid duplicacy, amendment in section 26 is proposed. To rationalize the assessment process, it is proposed to make uniform time barring period for all returns of a financial year by amending section 34.

TDS is deducted @ 4% in respect of registered dealers engaged in works contract. Amendment in section 36A is proposed to deduct TDS at a higher rate i.e. @ 6% from unregistered dealers for better compliance.

The designations of the officers in the department have been re-designated. Hence, the amendment in section 44.

The time barring period for disposal of the pending appeals pertaining to the Delhi Sales Tax Act, 1975 (since repealed) is ending on 31st March, 2013. It is proposed to extend the period by another two years by amending section 74. The appeals can then be disposed off next year through an amnesty scheme.

1205 DG/13-5

In the VAT regime, return filed by the dealer is treated as self-assessed. Department has prescribed an Audit Report for big dealers. To ensure compliance, it is proposed to enhance the penalty from Rs.10,000/- to Rs.1,00,000/- or one percent of the dealer's turnover, whichever is less, by amending section 86. This will help Department automate their refunds and avoid default assessments normally.

To give relief to the dealers, on their voluntarily disclosure of the tax deficiencies during field inspections and depositing the tax so due, from the penal provisions, amendment in section 87 is proposed.

(SHEILA DIKSHIT)
Chief Minister/Finance Minister

New Delhi :

Dated:

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2013 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2013 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

P. N. MISHRA, Secy.

HOME POLICE-II DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st March, 2013

No. F. 11/21/2000/HP-II/Pt.file/2244.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri A. K. Gaba, Senior Public Prosecutor, CBI, EO-II, New Delhi, to be the Public Prosecutor to conduct the prosecution in the Special Court constituted under the said Act in respect of case RC 220 2011 E 0004 EOU-VI under section 120B read with section 489B and 489C of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and under sub-section (2) of section 3 and section 4 of the said Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 as extended to NCT of Delhi, registered on 16-06-2011 in the Economic Offences-II Branch of Central Bureau of Investigation, Lodhi Road, New Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. K. TIWARI, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2013

No. F. 7(433)/Policy-II/VAT/2012/1429-38.—In supersession of Notification No. F. 7(433)/Policy-II/VAT/2012/585-595 dated 05-09-2012 and all the subsequent notifications regarding submission of information in Form T-2, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 70 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, hereby direct that the details of Invoice and Goods Receipt Note in respect of all goods purchased/received as stock transfer from outside Delhi, shall be submitted by the dealers online, using their login id and password, before the goods physically enter the boundary of Delhi. For this purpose, the revised Form T-2 annexed with this Notification shall be used.

This notification shall come into force as per following schedule :—

Class of Dealers	Effective date
Dealers having GTO \geq Rs. 10 Crores, except the dealers exclusively dealing in Tax Free Goods.	01-04-2013
All other dealers	To be notified later on.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

FORM T-2**Invoice Details:-**

Invoice No: Date: Total Invoice :
 Amount

Purchase Type:

Identity of Supplier :-

TIN :

Name :

Address :

State :

City:

Commodity Details :-

Total of Commodity wise details should be equal to the amount of purchase as recorded in DVAT-30.

Name of Commodity	Quantity	Unit	Rate per unit	Value
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total Amount:

Mode of Transport: ☐ By Road ☐ Through Courier ☐ By Train ☐ Through Pipeline ☐ By Air ☐ Through Internet

Dispatch Details :-

Place of Dispatch of Goods :

Place of Delivery of Goods :

Identity of Transporter:-

Name:

Address :

State :

City:

Vehicle No : (4 digit number)

GR/Airway/RR/Courier

Receipt

Date: